an>

Title: Problems arising due to the acquisition of land of farmers by the Government.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारा देश, कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन खाद्यान्न है। इस मुल्क में प्रति वर्ष तीन परसेंट उपजाऊ जमीन के क्षेत्रफल में कमी आती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि देश में सर्वांगीण विकास हो रहा है और जमीनें एक्वायर की जा रही हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, उसके द्वारा भी बहुत से राज्यों में, बहुत से विकास कार्यों हेतु, जमीनें एक्वायर की जा रही हैं, कहीं ताज हाइवे बन रहा है और कहीं गंगा हाइवे बन रहा है। इनमें लाखों हैक्टेयर जमीन एक्वायर की जा रही है। एक तरफ तो हम उद्योग बढ़ाकर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान की जमीन एक्वायर करने के कारण वह बेरोजगार हो रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें रोजगार ही देना है, तो जिस प्रकार से हरियाणा में जमीनें एक्वायर करने पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, उस तर्ज पर केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को मुआवजा दें। हरियाणा में 30 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। 10 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए रायल्टी प्रति वर्ष, प्रति एकड़ दी जा रही है तथा इसमें एक हजार रुपए का प्रति वर्ष इजाफा किया जा रहा है। इस प्रकार से जहां किसानों की जमीनें अधिगृहीत की जाएं, उनको उनकी जमीनों का हरियाणा प्रदेश के बराबर मूल्य दिया जाए या इस पर एक राष्ट्रीय नीति बने। जमीन देश की राष्ट्रीय सम्पदा है। इस पर भारत सरकार कोई राष्ट्रीय नीति बनाए, जिससे राज्य सरकारें और भारत सरकार जब किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करे, तो मार्केट रेट किसानों को उनकी जमीनों के मिलें और जब उनकी जमीन चली जाए, तो उन्हें रोजगार पर लगाएं, जिससे बेरोजगारी दूर हो और खाद्यान्न की कमी की भी हम पूर्ति कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।